टॉप कंपनियों की मार्केट पूंजी में उछाल

चार कंपनियों की वेल्यू 2.20 लाख करोड़ बढ़ी

नई दिल्ली, 4 मई मुंबई शेयर बाजार में बीते सप्ताह देश की शीर्ष कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला. जहां एक ओर कुछ बड़ी कंपनियों की वैल्यू में मजबूत बढ़त दर्ज की गई, वहीं कई दिग्गज कंपनियों के मार्केट कैप में गिरावट भी देखने को मिली.

इस मिश्रित रुझान के बावजूद कुल मिलाकर बाजार में निवेशकों की सक्रियता बनी रही और सेंटीमेंट स्थिर से सकारात्मक दिशा की ओर झुकता दिखाई दिया. रिपोर्ट के अनुसार, देश की टॉप 10 कंपनियों में से चार कंपनियों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में कुल 2.20 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई. इस बढ़त में सबसे बड़ा योगदान रिलायंस इंडस्ट्रीज का रहा. कंपनी का मार्केट कैप अकेले 1.39 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 19.36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो इसे इस अवधि का सबसे बड़ा लाभार्थी बनाता है. रिलायंस के इस प्रदर्शन को ऊर्जा, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में इसके मजबूत बिजनेस मॉडल और निवेशकों के भरोसे का संकेत माना जा रहा है.

इसके अलावा भारती एयरटेल ने भी बाजार में मजबूत प्रदर्शन किया. कंपनी के मार्केट कैप में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और इसका कुल मूल्य बढ़कर 11.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद एयरटेल की स्थिति मजबूत बनी हुई है, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है.

> रिपोर्ट के अनुसार मार्केट कैप में यह उतार-चढ़ाव वैश्विक आर्थिक संकेतों, कंपनियों के तिमाही नतीजों और निवेशकों की बदलती धारणा का परिणाम है. जहां कुछ सेक्टरों में मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहीं कुछ क्षेत्रों में दबाव बना हुआ है. कुल मिलाकर बाजार अभी भी अस्थिर लेकिन अवसरों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है.

किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ता लोन उपलब्ध

नई दिल्ली, 4 मई देश के किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक बड़ी राहत साबित हो रही है. इस योजना के तहत किसानों को खेती से जुड़े खर्चों के लिए आसान और सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य जरूरी कृषि कार्य बिना किसी वित्तीय परेशानी के पूरा कर सकते हैं.

इस योजना में किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है, जिस पर केवल 7 प्रतिशत की ब्याज दर लगती है. खास बात यह है कि अगर किसान समय पर लोन चुका देते हैं तो उन्हें 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत रह जाती है. यह सुविधा छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद लाभकारी मानी जा रही है.

तेल कीमतों में नरमी से बाजार उछला

वैश्विक राहत और सेक्टोरल फ्रंट पर दिखा तेजी का असर

प.एशिया में तनाव कम होने के संकेतों ने बाजार की धारणा को दी मजबूती

नई दिल्ली, 4 मई भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को मजबूत शुरुआत करते हुए निवेशकों को राहत भरा संकेत दिया. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेतों ने बाजार की धारणा को मजबूती दी.

इसके साथ ही घरेलू राजनीतिक घटनाक्रमों और विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझानों ने भी निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने का काम किया, जिससे प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में शुरुआती कारोबार के दौरान करीब 1 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. सेंसेक्स ने शुरुआती कारोबार में 833 अंकों की छलांग लगाते हुए 77,746.79 के इंट्राडे हाई को छू लिया. इसी तरह निफ्टी भी 250 अंकों की बढ़त के साथ 24,245.85 के स्तर पर पहुंच गया. यह तेजी बाजार में मजबूत खरीदारी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों का स्पष्ट प्रतिबिंब रही. सेक्टोरल फ्रंट पर भी व्यापक खरीदारी देखने को मिली. ऑटो, रियल्टी, मेटल, एफएमसीजी और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी. निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मेटल, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में लगभग 2 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई, जिससे यह साफ हुआ कि बाजार में व्यापक आधार पर तेजी का माहौल बना हुआ है.हालांकि, हर सेक्टर में समान उत्साह नहीं देखा गया. कुछ बड़े शेयरों पर दबाव भी बना रहा. कोटक महिंद्रा बैंक, डॉ. रेड्डीज लैबोरेट्रीज, टीसीएस, आईटीसी और भारती एयरटेल जैसे प्रमुख स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली, जिससे यह संकेत मिला कि बाजार में चुनिंदा मुनाफावसूली भी जारी है.

अदाणी समूह को बड़ी कानूनी जीत हासिल हुई

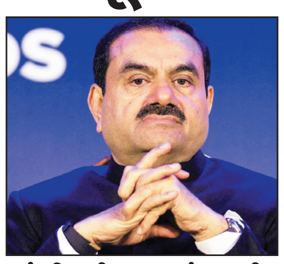

नई दिल्ली, 4 मई. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के दिवालियापन मामले में अदाणी समूह की 14,535 करोड़ रुपए की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे अदाणी समूह को बड़ी कानूनी जीत हासिल हुई है.

न्यायाधिकरण ने वेदांता समूह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने तर्क दिया था कि उसकी बोली वित्तीय रूप से बेहतर थी. एनसीएलएटी ने स्पष्ट किया कि लेनदारों की समिति द्वारा वेदांता की योजना को अस्वीकार करना पूरी तरह उचित था और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई.

एनसीएलएटी ने 24 नवंबर 2025 को हुई सीओसी की 24वीं बैठक के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि समिति के व्यावसायिक विवेक में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि समाधान योजना के किसी भी चरण में प्रक्रिया पूरी तरह वैध रही और समिति के निर्णय को बनाए रखना न्यायसंगत था.

पहली नौकरी में समझदारी निवेश योजना

नई दिल्ली, 4 मई पहली नौकरी अक्सर उत्साह और नई आजादी लेकर आती है, लेकिन यही समय भविष्य की मजबूत वित्तीय नींव रखने के लिए सबसे अहम भी होता है. वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यदि करियर की शुरुआत में ही लक्ष्य आधारित निवेश रणनीति अपनाई जाए, तो सीमित आय में भी बड़े सपनों को पूरा किया जा सकता है. एक युवा बैंक अधिकारी के उदाहरण से यह समझा जा सकता है कि कैसे सही योजना बनाकर बहन की पढ़ाई, शादी, खुद का घर और कार जैसे बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं. किसी भी निवेश की शुरुआत आपातकालीन निधि (इमरजेंसी फंड) से करनी चाहिए, जिसमें कम से कम छह महीने के आवश्यक खर्च की राशि सुरक्षित रखी जाए.

सोना सस्ता हुआ, चांदी के दाम बढ़े

200 रुपए सस्ता हुआ सोना

500 रुपए महंगी हुई चांदी

नई दिल्ली, 4 मई हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. जहां सोने के दामों में 200 रुपए गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी के भाव में 500 रुपए की बढ़ोतरी ने निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस बदलाव का असर देशभर के ज्वैलरी बाजारों में साफ दिखाई दिया.

जानकारों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के चलते सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है. इसी वजह से घरेलू बाजार में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, यह गिरावट बड़ी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए यह एक अहम संकेत माना जा रहा है.

वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी और वैश्विक सप्लाई में हल्की कमी के कारण चांदी के भाव ऊपर गए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर में बढ़ती मांग भी चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर रही है.

सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमतों में आज प्रति 10 ग्राम पर हल्की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के रेट प्रति किलोग्राम बढ़ गए हैं. इस बदलाव से जहां खरीदारों के लिए सोना कुछ सस्ता हुआ है, वहीं चांदी की बढ़ी कीमतें निवेशकों के लिए मुनाफे का संकेत दे रही हैं.

आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति सोने-चांदी की कीमतों को और प्रभावित कर सकती है. फिलहाल बाजार में स्थिरता की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अस्थिरता की संभावना भी बनी हुई है.

देश में एलपीजी आपूर्ति सामान्य स्थिति में बरकरार

सरकार ने घबराहट में खरीदारी से बचने की अपील की

मांग के अनुसार लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है

नई दिल्ली, 4 मई देश में ईंधन और रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी सप्लाई पूरी तरह सामान्य और स्थिर बनी हुई है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है.

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करें, क्योंकि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई चेन पूरी तरह सुचारू रूप से काम कर रही है.

मंत्रालय के अनुसार, 2 मई को ही देशभर में लगभग 47.7 लाख एलपीजी सिलिंडरों की बुकिंग हुई, जिनमें से करीब 47 लाख सिलिंडरों की डिलीवरी सफलतापूर्वक पूरी की गई. यह आंकड़ा दर्शाता है कि वितरण व्यवस्था मजबूत बनी हुई है और मांग के अनुसार लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. सरकार ने यह भी कहा कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी के लिए 100 प्रतिशत आपूर्ति बनाए रखने का लक्ष्य पूरी तरह पूरा किया जा रहा है.

सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें.

> सरकार ने यह भी बताया कि एलपीजी की जमाखोरी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए देशभर में व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं. शनिवार को अकेले 1900 से अधिक छापे मारे गए, जिनमें कई अनियमितताएं सामने आईं. इसके बाद 349 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया गया और 74 वितरकों को निलंबित भी किया गया है. यह कार्रवाई आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए की जा रही है.

एआई चैटबॉट स्कैम से यूजर्स परेशान

नई दिल्ली, 4 मई डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के बीच अब एक नया साइबर फ्रॉड सामने आया है, जिसमें एआई चैटबॉट्स के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है.

इस स्कैम में यूजर्स के बैंक कार्ड से बिना अनुमति के पैसे कट जाते हैं, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह ट्रांजैक्शन सामान्य और वैध लगते हैं, जिससे शुरुआती स्तर पर धोखाधड़ी पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्कैम खासतौर पर उन लोगों को निशाना बना रहा है जो एआई चैटबॉट और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं. कई मामलों में यूजर खुद किसी एआई सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेकिन बाद में उसी प्लेटफॉर्म के नाम पर अतिरिक्त और अनधिकृत चार्जेस शुरू हो जाते हैं. इससे लोगों को लगता है कि यह नियमित बिलिंग का हिस्सा है, जबकि असल में यह फर्जी ट्रांजैक्शन होते हैं.

> साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्कैम पारंपरिक फ्रॉड से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें वैध प्लेटफॉर्म का नाम और सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि इसे पकड़ पाना आसान नहीं है. कई लोग तब तक नुकसान झेल चुके होते हैं जब तक उन्हें असली स्थिति का पता चलता है.

इस धोखाधड़ी का तरीका भी काफी चतुर बताया जा रहा है. जैसे ही कोई यूजर किसी चैटबॉट सेवा का भुगतान करता है, उसका कार्ड सिस्टम में सेव हो जाता है.

चावल, चीनी, खाद्य तेलों के भाव टूटे, दालों में घट-बढ़

नयी दिल्ली. घरेलू थोक जिंस बाजारों में सोमवार को चावल का औसत भाव गिर गया. चावल के साथ चीनी और खाद्य तेलों में भी नरमी देखी गयी. गेहूं में टिकाव रहा जबकि दालों के दामों में घट-बढ़ रही. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत चार रुपये घटकर 3,832 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी. गेहूं 2,781 रुपये प्रति क्विंटल पर लगभग अपरिवर्तित रहा. आटे की कीमत 12 रुपये गिर गयी. दाल-दलहनों में उतार-चढ़ाव रहा. चना दाल की औसत कीमत नौ रुपये और मसूर दाल की चार रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी.

आधार अपडेट महंगा, कुछ सेवाएं अब नि :शुल्क

नई दिल्ली, 4 मई आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या फोटो जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों को अद्यतन कराना अब पहले की तुलना में अधिक खर्चीला हो गया है, क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपनी सेवाओं के लिए नए शुल्क निर्धारित किए हैं.

हालांकि इसके साथ ही कुछ ऐसी सुविधाएं भी जारी रखी गई हैं, जिनके तहत नागरिकों को सीमित अवधि तक नि:शुल्क सेवाओं का लाभ मिल सकता है. वर्तमान समय में आधार केवल पहचान पत्र नहीं, बल्कि बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है, ऐसे में इसकी जानकारी को सही और अद्यतन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है. नई व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने आधार में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल जैसी जनसांख्यिकीय जानकारी में बदलाव कराना चाहता है, तो इसके लिए प्रति बार 75 रुपये का शुल्क देना होगा.

समाचार विशेष

क्या भाजपा का चक्रव्यूह भेद पाएगी आप?

चंडीगढ़. राज्यसभा सांसदों के दल बदल के साथ ही भाजपा ने पंजाब में अपना कूटनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है. यह कोई हैरत की बात नहीं हैं, क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी भाजपा ने इसी रणनीति से काम करते हुए शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के कई आला नेताओं को अपने पाले में किया था.

उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी इसलिए भाजपा का निशाना कांग्रेस थी मगर अबकी बार व्यूह रचना सत्तारूढ़ आप के लिए है. इसी कूटनीतिक चक्रव्यूह से उभर कर सत्ता वापसी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. इसके लिए पार्टी को नए सिरे से चुनावी रणनीति तैयार कर मैदान में उतरेगी. इसकी बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया, सीएम भगवंत मान और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमर अरोड़ा के कंधों पर होगी. पंजाब में पार्टी का संगठन मजबूत है और साल 2022 में प्रचार का तरीका भी आक्रामक रहा था. सूबे में चुनाव लड़ने के लिए अच्छा फंड भी मिला था और विदेशों में बैठे एनआरआई पंजाबियों ने खुलकर समर्थन किया था.अब साल 2027 के लिए चुनौती इसलिए बड़ी दिख रही है क्योंकि साल 2022 के चुनावी रणनीतिकारों में से दो बड़े नेता एवं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संदीप पाठक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं. आप के सिपाही से भाजपाई बनने वाले सात राज्यसभा सांसदों में से छह पंजाब कोटे के हैं इसलिए इसका भी विपरित असर आप पर पड़ना लाजिमी है.

इस उठापटक से न तो पार्टी कार्यकर्ता व नेता भटकें और न ही मकसद. इसके लिए पार्टी हाईकमान बहुत गंभीर है. इस घटनाक्रम के बाद सीएम कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर उन्हें यह कहकर समझा रहे हैं कि आप एक समुद्र है और यदि कोई उसमें से एक गड़वी (लोटा) पानी भर ले तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता

> **घेराबंदी का तोड़ जरूरी**
> आप की निगाहें साल 2027 के चुनाव जीतकर सत्ता वापसी पर है मगर भाजपा फिलहाल आप समेत अन्य दलों के लिए भी कसमसाहट पैदा कर रही है. आप ने सभी दलों के नेताओं को भाजपाई बनने के लिए खुला न्योता दे दिया है. आप को यदि अपना लक्ष्य हासिल करना है तो अपनों को संभालते हुए इस घेराबंदी को तोड़ना होगा क्योंकि यदि पार्टी बिखरती है और संगठन कमजोर होता है तो आप की चुनौती और बढ़ जाएगी.

राजस्थान में राज नहीं रिवाज बदलने की तैयारी

नितिन नवीन का मंत्र क्या तोड़ पाएगा

जयपुर. राजस्थान की राजनीति में एक कहावत मशहूर है- यहां की जनता राज नहीं, रिवाज पर चलती है. पिछले तीन दशकों से मरूधरा की सियासत एक रिवॉल्विंग डोर की तरह घूम रही है, जहां हर पांच साल में सत्ता की चाबी एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है.

लेकिन क्या अब इस तीन दशक पुराने मिथक के टूटने का समय आ गया है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित कोर कमेटी और प्रदेश कार्यकारिणी की मैराथन बैठक में यही हुंकार भरी. उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दो टूक शब्दों में सरकार रिपीट का मंत्र दिया.

राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की यह परिपाटी 1993 के चुनाव के बाद से पत्थर की लकीर बनी हुई है. भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा ने लगातार दो बार सरकार बनाकर इतिहास रचा था. यह आखिरी मौका था जब किसी दल ने सत्ता बरकरार रखी थी. इतिहास के पन्नों को पलटें तो पिछले 30 सालों में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज नेता भी इस एंटी-इंकमबेंसी के किले को नहीं ढहा पाए. मतदाता हर पांच साल में भाजपा को हटाकर कांग्रेस और कांग्रेस को हटाकर भाजपा को सत्ता सौंपते रहे हैं.

नितिन नवीन ने टोंक के दौरे और जयपुर की बैठक में साफ कहा कि राजनीति 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को शॉर्टकट से बचने की सलाह देते हुए कहा कि यहां स्पीड का नहीं, बल्कि स्टेमिना का टेस्ट होता है.

> **केंद्र और राज्य की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना**
> बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित भाजपा के तमाम दिग्गज मौजूद रहे. नवीन ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश इकाई की पीठ थपथपाई. उनका सीधा मंत्र है कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना.

उद्धव ठाकरे जाएंगे विधान परिषद!

मुंबई. महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिव सेना और कांग्रेस पार्टी ने मिल कर शरद पवार को राज्यसभा भेजा. अब कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी मिल कर उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में भेजेंगे.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे से अपील की है कि वे विधान परिषद में जाएं. गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे 2019 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद संवैधानिक अनिवार्यता के तहत वे विधान परिषद के सदस्य बने थे.अब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है. राज्य में विधान परिषद की नौ सीटें खाली हो रही हैं.

इसके अलावा एक उपचुपनाव की सीट भी है. विधानसभा के मौजूदा गणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को चार सीट मिलेगी. उसकी दोनों सहयोगी पार्टियों शिव सेना और एनसीपी को दो दो सीटें मिलेंगी.

एक सीट विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के खाते में जाएगी. कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी दोनों चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उच्च सदन में जाएं.

विशेष सपा की जातीय राजनीति को विकास की राजनीति के साथ जवाब देने की तैयारी

मोदी-योगी ने तैयार की पीडी वाली रणनीति

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाया गया है. पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही प्रदेश में चुनावी माहौल बनता दिख रहा है. भले ही चुनाव 2027 के फरवरी मार्च में होने वाले हैं लेकिन रणनीति अभी से तैयार की जा रही है.

विपक्षी दल समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमाए गए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए चुनावी मैदान में उतरती दिख रही है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है. अखिलेश यादव के पीडीए पॉलिटिक्स के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीडी यानी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी जीत की हैट्रिक बनाने की तैयारी में जुटे दिख रहे हैं. यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी की जातीय राजनीति को विकास की राजनीति के साथ जवाब देने की तैयारी है.

इसके अलावा महिला आरक्षण के मुद्दे को भाजपा ने जोर-शोर से छेड़ दिया है. प्रोग्रेस, डेवलपमेंट के साथ वीमेन का मुद्दा गरमाया हुआ है. यही साथ ही, चुनावी माहौल गरमाने के बाद भाजपा हिंदुत्व वाली राजनीति की तरफ शिफ्ट होती दिख सकती है. बंगाल में जिस प्रकार से चुनावी मैदान में हिंदुत्व का मुद्दा गरमाया. 4 मई को विधानसभा चुनावों के रिजल्ट के बाद इस दिशा में भाजपा बड़े स्तर पर काम करती दिख सकती है.

विकास वाली राह पर मोदी-योगी- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के राजनीतिक मैदान में पिछले एक माह में कई बार उपस्थिति दर्ज कराई है. नोएडा में सेमीकंडक्टर प्लांट के शिलान्यास समारोह से लेकर मेरठ से मेरठ मेट्रो एवं आरटीएस प्रोजेक्ट, फिर ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके बाद सहारनपुर में यूपी खंड के देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के जरिए पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने विकास वाली राजनीति पर विशेष जोर दिया गया.

सीएम योगी की बड़ी रणनीति- वहीं, वाराणसी में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और हरदोई से 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने की बात कर चुके हैं. इस दिशा में लगातार प्रयास करते दिखे हैं. साथ ही, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सख्त एक्शन और बेहतर कानून व्यवस्था के जरिए विदेशी निवेशकों का ध्यान खींचा जा रहा है.

> **लगातार बदल रही रणनीति**
> यूपी चुनाव 2027 को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है. विकास वाली राजनीति के आधार पर वोटरों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि, संवेदनशील मुद्दे चुनावी रुख को मोड़ने में कामयाब होते हैं. ऐसे में माहौल बनाने और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने के लिए भाजपा की ओर से महिला आरक्षण का उठाया गया मुद्दा काम करता दिख रहा है. ऐसे में विकास योजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास के जरिए भाजपा सरकार अपने कामों को जमीन पर दिखाने की कोशिश में जुटी दिख रही है.